

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 00597 / 2023

अमृत लाल

—अपीलार्थी

## बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सचिवालय (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग, भरतपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बामनी, धौलपुर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2023  
आदेश की दिनांक : 01.02.2023

## उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीन्द्र कुमावत, अभिभाषक  
प्रत्यर्थागण की ओर से :

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य  
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बदरिका, धौलपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक-1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामनी, भरतपुर में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 200 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी की पत्नी वर्तमान अध्यापक ग्रेड-3 के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बारा/मालोनी खुर्द, सैनपड, धौलपुर में कार्यरत है तथा अपीलार्थी के एक वर्ष की बच्ची है जिसकी देखभाल के लिए अपीलार्थी एवं उनकी पत्नी के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं है बच्ची की देखभाल की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया,

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बदरिका, धौलपुर में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा-निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)  
सदस्य

(शुचि शर्मा)  
सदस्य

